प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 17th सितंबर, 2025

दूरस्थ लेखापरीक्षण की ओर रणनीतिक बदलाव: सार्वजनिक लेखापरीक्षण में उत्कृष्टता हेतु

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) लेखापरीक्षा आच्छादन बढ़ाने, लेखापरीक्षिती परिसर में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए समय कम करने और लेखापरीक्षा परिणामों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दूरस्थ एवं मिश्रित लेखापरीक्षा के लिए प्रणाली-व्यापी रणनीतिक बदलाव कर रहे हैं। वर्तमान में, डिजिटल एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की परिपक्वता और पहुंच सरकार के विभिन्न स्तरों, विभागों और प्रक्रियाओं में काफी भिन्न होती है। जहां भी डेटा की गुणवत्ता, पूर्णता और पर्याप्तता और विश्वसनीयता युक्तिसंगत है और डेटा/सिस्टम तक पहुंच लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध है, वहां आद्योपांत तक दूरस्थ लेखापरीक्षा करने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं। अन्य मामलों में, मिश्रित लेखापरीक्षाएँ की जाती हैं जो मुख्य रूप से हमारे कार्यालयों में उपलब्ध आंकडों और अभिलेखों के आधार पर डेस्क-आधारित समीक्षा के माध्यम से की जाती हैं और केवल मूल लेखापरीक्षा के लिए लक्षित क्षेत्र का दौरा किया जाता है।

यह परिवर्तन जोखिम आधारित योजना, शासकीय मंचों तक सुरक्षित पहुंच (जैसे आईएफएमएस, ई-प्रोक्योरमेंट और सार्वजनिक कार्यों के लिए डब्ल्यूएएमआईएस जैसे क्षेत्रीय डेटाबेस) और सभी क्षेत्रों में साक्ष्य और स्थिरता को मजबूत करने के लिए पीएम गतिशक्ति जैसे भू-स्थानिक उपकरणों के उपयोग पर आधारित है।

दूरस्थ लेखापरीक्षण में नवाचार

कई लेखापरीक्षा क्षेत्रों में दूरस्थ लेखापरीक्षा के पायलट अध्ययन संपन्न हो चुके हैं, और अब उन्हें सभी कार्यालयों में दोहराया जा रहा है। उच्च स्वचालन, समृद्ध और मानकीकृत डेटा के कारण प्राप्ति लेखापरीक्षा में दूरस्थ लेखापरीक्षा तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें एक मानकीकृत लेखापरीक्षा अभिकल्प आव्यूह एवं केंद्रीय रूप से मान्य एसक्यूएल क्वेरी का उपयोग करके केंद्र और राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों में समवर्ती रूप से किया जाने वाला डेटा-आधारित जीएसटी लेखापरीक्षा शामिल है। इसी प्रकार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तेलंगाना, द्वारा स्टाम्प एवं पंजीकरण

विभाग के दूरस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा से वास्तविक समय समन्वय के साथ सफल कार्यालय-आधारित संवीक्षा का प्रदर्शन किया जाता है।

व्यय पक्ष पर, मिश्रित लेखापरीक्षाएँ की जा रही हैं, जिसमें कार्यालयों में प्राप्त भौतिक अभिलेखों को डेटा विश्लेषण के साथ संयोजित किया जाता है। हाल ही में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा द्वारा लोक निर्माण लेखापरीक्षा में पायलट परियोजना का प्रदर्शन किया गया तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों को इस दृष्टिकोण के बारे में सूचित किया गया तथा इस पहल को दोहराने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) के दूरस्थ लेखा-परीक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की जा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल की आभासी लेखापरीक्षा प्रणाली को लेखापरीक्षा ऑनलाइन के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे कागज रहित पं.रा.सं. प्रमाणीकरण संभव हो गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन के अंतर्गत निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डीएलएफए) द्वारा दूरस्थ प्रमाणीकरण के लिए एक रोडमैप विकसित कर रहा है।

प्रत्येक क्षेत्र के लिए मौजूदा आंकड़ा भंडारों और ऐतिहासिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उपयोग करते हुए जोखिम मूल्यांकन मॉडल विकसित किए जा रहे हैं, जिससे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर तीव्र ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। पैटर्न की पहचान करने, परिचालन समूहों को समझने तथा अधिक सटीकता के साथ विसंगतियों का विश्लेषण करने के लिए आईएफएमएस और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल सहित शासकीय मंचों का लाभ उठाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में इसे सुगम बनाने के लिए, 20 से अधिक डेटाबेस तक पहुंच और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तक ऑनलाइन पहुंच प्राप्त की गई है।

सीएजी-कनेक्ट पोर्टल: हितधारक सहभागिता को सुगम बनाने हेतु

शीघ्र ही लांच होने वाला सीएजी-कनेक्ट पोर्टल लगभग 10 लाख लेखापरीक्षित संस्थाओं को लेखापरीक्षा प्रश्नों, टिप्पणियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों का सीधे उत्तर देने के लिए एकीकृत डिजिटल इंटरफेस प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-सक्षम और सभी हितधारकों के लिए उनकी भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखे बिना सुलभ बनाएगा, जिससे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और लेखापरीक्षित संस्थाओं दोनों द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उचित नज़र रखने में मदद मिलेगी और साथ ही त्वरित समाधान की सुविधा भी मिलेगी।

सीएजी-एलएलएम: बेहतर लेखापरीक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

सीएजी-एलएलएम (वृहद भाषा मॉडल) नामक एक पहल विकासाधीन है, जिसे लेखापरीक्षकों को दशकों के संस्थागत ज्ञान तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लेखापरीक्षा विश्लेषण में दक्षता और स्थिरता में सुधार होगा। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित प्रणाली बड़े डेटासेट और आंतरिक रूप से तैयार किए गए दस्तावेजों जैसे निरीक्षण प्रतिवेदन का विश्लेषण करने में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगी, बढ़ी हुई सटीकता के साथ पैटर्न और जोखिमों की पहचान करेगी, और लेखापरीक्षकों को अधिक गहन लेखापरीक्षा अंतर्दृष्टि और व्यापक प्रतिवदेन तैयार करने में सहायता करेगी।

संपूर्ण डिजिटल परिवर्तन की दूरदर्शिता

भविष्य की ओर देखते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने समर्पित आंतरिक डिजिटल परिवर्तन अधिकारियों के माध्यम से संपूर्ण लेखापरीक्षा और लेखा पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक डिजिटल परिवर्तन की परिकल्पना की है। विभिन्न राज्यों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित डेटा विश्लेषण सेल के साथ मिलकर काम करते हुए, ये अधिकारी ऐसे नवाचारों का नेतृत्व करेंगे जो दूरस्थ एवं मिश्रित लेखापरीक्षा के पैमाने और पहुंच को बढ़ाएंगे। ये केंद्र उन्नत लेखापरीक्षा अभ्यास केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेंगे तथा विभिन्न सरकारी प्रणालियों के साथ वास्तविक समय एकीकरण को सक्षम करेंगे।

रणनीतिक रूप से, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, लेखापरीक्षा पहुंच का विस्तार करके, तथा डिजिटल मंचो के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक दूरस्थ लेखापरीक्षा के लिए एक महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, जो जवाबदेह, डेटा-संचालित और नागरिक-केंद्रित है, तथा सार्वजनिक क्षेत्र की निगरानी और पारदर्शिता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है।

BSC/SS/IK/63-25